सरकारी कर्मचारियों के वेतन से न्यू पेंशन स्कीम की 10 फीसदी राशि कटौती 1 अप्रैल से बंद

कर्मचारियों का जो पैसा अब तक जमा हो चुका, वह आरजीएचएस में समायोजित करने के बाद रिटायरमेंट के वक्त ब्याज समेत मिलेगा

-विधानसभा संवाददाता-

■ खिलाड़ियों को 40 साल की उम्र के बाद प्रतिमाह 20 हजार रु. पेंशन देगी राज्य सरकार

■ महिलाओं को कर्ज देने के लिए जयपुर में बनेगा महिला को-ऑपरेटिव बैंक, सरकार देगी 250 करोड़ का फंड

जयपुर। न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) को खत्म करके पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब 1 अप्रैल से कर्मचारियों के वेतन से 10 फीसदी रकम कटौती खत्म करने की घोषणा भी कर दी है। जनवरी 2004 से भर्ती हुए सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन से अब हर माह होने वाली 10 फीसदी कटौती नहीं होगी। इसके पहले हुई जो रकम कर्मचारियों की काटी गई है, उसे पेंशनर्स मेडिकल फंड की राशि (आरजीएचएस) में समायोजित करने के बाद बचे हुए पैसे को रिटायरमेंट के वक्त ब्याज सहित दिया जायेगा। सोमवार को विधानसभा में राजस्थान वित्त एवं विनियोग विधेयक-2022 पर बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की।

गहलोत ने कहा कि 1 अप्रैल से सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा। न्यू पेंशन की 10 फीसदी रकम कटौती खत्म होने से हर कर्मचारी को प्रतिमाह 2000 से लेकर 10 हजार रुपए तक ज्यादा रकम मिलेगी। गहलोत ने बजट में 2004 और उसके बाद भर्ती कर्मचारियों पर लागू न्यू पेंशन स्कीम खत्म कर इसी साल से 1 अप्रैल से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की थी। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी के मूल वेतन से 10 फीसदी पैसा एनपीएस के लिए काटा जाता था, उतना ही पैसा सरकार मिलाती थी।

मुख्यमंत्री ने इसके अलावा भी कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने खिलाड़ियों के लिए पेंशन योजना लागू करने का ऐलान किया। इसके तहत खिलाड़ियों को 40 वर्ष की उम्र पूरी करने पर 20 हजार प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। पेंशन के लिए पात्रता के नियम अलग से जारी किए जाएंगे। महिलाओं को कर्ज देने के लिए जयपुर में अलग से महिला कोऑपरेटिव बैंक खोला जाएगा। इस बैंक को राज्यसरकार शुरुआत में 250 करोड़ रुपए का फंड देगी।

अधिवक्ता की लापता पुत्रियों की बरामदगी नहीं होने पर वकीलों ने लगाया जाम

वकील की पुत्रियों को 45 दिन बाद भी नहीं खोजने पर अधिवक्ताओं ने सोमवार को जयपुर में हाईकोर्ट के बाहर और कलेक्ट्री के बाहर जाम लगाया।

■ अधिवक्ता की लापता पुत्रियों की बरामदगी नहीं होने पर वकीलों ने लगाया जाम

■ अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रथम अजयपाल लांबा के नेतृत्व में 16 पुलिसकर्मियों की एसआईटी गठित

■ 45 दिन से लापता पुत्रियों का आज तक पता नहीं लगा पाई पुलिस

जयपुर, (का.सं.)। शहर के एक अधिवक्ता की करीब 45 दिन से लापता दो पुत्रियों की बरामदगी नहीं होने पर वकीलों ने शहर के दो मुख्य मार्गों पर जाम लगा दिया। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने मामले में एसआईटी गठित कर लापताओं की तलाश के प्रयास शुरू कर दिए हैं। दी बार एसोसिएशन के बैनर तले वकीलों ने सेशन कोर्ट के बाहर एमआई रोड को जाने वाली सड़क पर प्रदर्शन किया और जाम लगा दिया। इसी तरह हाइकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी हाईकोर्ट के बाहर बीच सड़क पर टैंट लगाकर रास्ते को अवरूद्ध कर दिया। एक ही समय दो मुख्य मार्ग जाम होने के चलते शहर का यातायात भी कई घंटों तक अव्यवस्थित रहा। दोनों बार एसोसिएशन ने तीन दिन पूर्व मुख्यमंत्री सहित प्रशासन को इस संबंध में लिखित में अल्टीमेटम दे दिया था।

हाईकोर्ट के बाहर जाम की सूचना मिलने पर पुलिस के कई आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने वकीलों को समझाने का प्रयास किया। वहीं मामले में डीजीपी ने अतिरिक्त पुलिस आयुक्त जयपुर प्रथम अजय पाल लांबा के नेतृत्व में 16 पुलिसकर्मियों की एसआईटी गठित की गई है। इस टीम के द्वारा की गई कार्रवाई की रोजाना पुलिस आयुक्त को सूचना देनी होगी। वहीं एसओजी और एटीएस के अतिरिक्त महानिदेशक एसआईटी को सभी तकनीकी और ऑपरेशनल सहयोग उपलब्ध कराएंगे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव गिर्राज शर्मा ने बताया कि अधिवक्ता अवधेश कुमार पुरोहित की 16 और 17 साल की दो बेटियां रमा और भावना करतारपुरा स्थित लाईसीएम सीनियर सैकण्डरी स्कूल से गत तीन फरवरी को लापता हो गई थी। इसे लेकर महेश नगर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई, लेकिन दोनों बच्चियों को अब तक बरामद नहीं किया गया है। दोनों की आखिर लोकेशन लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन और निशातगंज पेपर मिल कॉलोनी की आई थी। इसके बावजूद पुलिस मामले में प्रभावी कदम नहीं उठा रही है। बार एसोसिएशन ने दोनों बच्चियों की सूचना देने पर 51 हजार रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा भी की है। वहीं दी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल किशोर शर्मा और डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने बताया कि दोनों बच्चियों को लापता हुए डेढ़ माह से ज्यादा समय बीत चुका है। यदि अब भी लापता बेटियां बरामद नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। गौरतलब है कि अधिवक्ता अवधेश कुमार की 17 और 16 साल की दो पुत्रियां रमा और भावना 3 फरवरी को बीमारी की बात कहकर स्कूल से निकली थी। वहीं बाद दोनों लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन और फिर निशातगंज पेपर मिल कॉलोनी में भी अकेली घूमते सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुई हैं। मामले में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखकर त्वरित कार्रवाई करने की बात कही है।

सरकार की अन्य घोषणाएं

- ❖ फूड सेफ्टी निदेशालय बनेगा।
- ❖ 500 स्कूलों में नए संकाय खुलेंगे।
- ❖ बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू होगी, इसमें पूरा खर्च को रिएम्बर्स किया जाएगा।
- ❖ 9 से 12 वीं तक की कक्षाओं के लिए 50 करोड़ की लागत से ई लाइब्रेरी।
- ❖ 2 लाख बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी।
- ❖ शांति व अहिंसा निदेशालय पर 5 करोड़ खर्च होंगे।
- ❖ खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना लागू होगी, 18 करोड़ खर्च होंगे।
- ❖ अगले साल से राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता, ग्रामीण ओलिंपिक भी होगा।
- ❖ ग्रामीण ओलिंपिक में पदक जीतने वालों को पंचायत स्तर पर संविदा भर्तियों में प्राथमिकता।
- ❖ अगले साल 5000 नई राशन की दुकानें खोली जाएंगी।
- ❖ स्कूलों में बच्चों को मिड-डे-मील में दो दिन दूध दिया जाएगा। इस पर 500 करोड़ रु. खर्च होंगे।
- ❖ शहरों में लिक्विड कचरे से मीथेन गैस बनाने के प्लांट लगेंगे।
- ❖ प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टा मिलने के 3 साल बाद अब जमीन-मकान बेच सकेंगे, पहले 10 साल तक बेचने पर प्रतिबंध था।
- ❖ मंडियों पर 0.5 फीसदी यूजर चार्ज को घटकर 0.2 फीसदी करने की घोषणा।
- ❖ डेयरी संघों को निर्देशित किया जाएगा कि दूध के दाम नहीं बढ़ाएं जाएं।
- ❖ बारां में डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी।
- ❖ ईटीटी प्रयोगशालाएं लगेंगी।
- ❖ खारे पानी से झींगा उत्पादन को देखते हुए चूरू में मत्स्य पालन विभाग का दफ्तर खुलेगा।
- ❖ चूरू किले के जीर्णोद्धार के लिए 5 करोड़ रु. की घोषणा।
- ❖ क्रेडिट कॉपरेटिप सोसाइटीज की ठगी रोकने के लिए वित्त विभाग के अधीन अलग से डायरेक्ट्रेट ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंस बनाने की घोषणा।
- ❖ जमीनों की धोखाधड़ी रोकने के लिए सोसाइटी एक्ट में संशोधन होगा।
- ❖ 57 पंचायत समित मुख्यालयों पर सीडीपीओ, बीसीएमएचओ दफ्तर खुलेंगे।

'बजट घोषणाओं को लागू करेंगे, नहीं तो हम बदनाम होंगे, विपक्ष को चिंता क्यों?'

-विधानसभा संवाददाता-

■ अशोक गहलोत ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष समेत तमाम बीजेपी विधायकों पर कटाक्ष किया

■ बीजेपी की मार्केटिंग में मास्टरी, हम काम ज्यादा करते हैं, मार्केटिंग कम। कर्ज चुकाने की औकात है, इसलिए ले रहे, औकात से ज्यादा कर्ज की इजाजत भारत सरकार से नहीं मिलती : मुख्यमंत्री

■ गहलोत ने कहा कि ''बीजेपी के नेताओं में मोदी और अमित शाह का डर बैठा हुआ है, इसलिए वे राजस्थान की ईआरसीपी को केंद्रीय परियोजना घोषित करवाने की मांग नहीं उठा रहे। हमारे साथ चलिए, कम से कम इसमें तो पैरवी कर दीजिए, केन्द्रीय जलमंत्री भी राजस्थान के हैं।''

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में कहा कि पूरे बजट सत्र में विपक्ष बार-बार कहता रहा है कि बजट कैसे लागू होगा? लेकिन आप चिंता क्यों करते हैं हमारी सरकार की। बजट हम लागू नहीं करेंगे तो बदनाम हम होंगे। विपक्ष को हमारी फिक्र क्यों है। आप क्या आगाह करोगे, जब कोई तर्क लगता हो तो आगाह कीजिए। मैंने बजट घोषणाओं पर बैठक ले ली। 100 प्रशासनिक मंजूरियां निकाल दी हैं। हमारा वित्तीय प्रबंधन शानदार है। खर्चा हो रहा है, इसका मतलब काम हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह कटाक्ष सोमवार को सदन में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया समेत तमाम बीजेपी विधायकों पर किया।

गहलोत ने तंज कसा कि विपक्ष जानबूझकर बोल रहा है कि बजट लागू कैसे होगा? बीजेपी की तो मास्टरी है कि मार्केटिंग शानदार करनी है, चाहे काम कम करो। हम काम में लगे रहते हैं, मार्केटिंग नहीं करते हैं। बजट को लेकर विपक्ष ने सदन के अंदर आंकड़ों के खेल में फंसाकर रखा। बजट लागू नहीं होगा, यह कहकर अलग माहौल बनाने कर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई अलग है।

गहलोत ने कहा कि भारत सरकार की मंजूरी के बिना कर्ज नहीं ले सकते। जीएसडीपी हाई होगी तो कर्ज ज्यादा मिलेगा। आप भार बढ़ने की बात कैसे कह सकते हैं? देश और दुनिया की सरकारें भारी कर्ज लेकर विकास करती हैं। कर्ज उसी लिमिट में लिया जाता है, जिस लिमिट में चुकाने की कैपिसिटी हो, राज्य सरकार उससे ज्यादा ले ही नहीं सकती, इसलिए कर्ज का भार बढ़ने की बात गलत है। कर्ज उतना ही ले सकते हैं जितनी औकात है, हमारी कर्ज चुकाने की औकात है, इसलिए कर्ज ले रहे है।

मुख्यमंत्री ने कहा, केन्द्र की मोदी सरकार का राज्यों के प्रति रवैया ठीक नहीं है। हमारे हिस्से का केंद्र सरकार से 68 हजार करोड़ रु. मिलना चाहिए था, लेकिन मोदी सरकार केवल 49 हजार करोड़ रु. ही देगी। यानि कि पूरा 19 हजार करोड़ रु. राजस्थान को कम मिलेगा।

ज्ञानचंद पारख ने मोदी की तुलना भगवान शिव से की तो सदन में हंगामा मचा

■ कांग्रेस विधायक और जलदाय मंत्री महेश जोशी बोले ''यह हिंदुओं की आस्था का अपमान है''

जयपुर (विसं)। विधानसभा में सोमवार को उस वक्त हंगामा मच गया, जब पाली के विधायक ज्ञानचंद पारख ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तुलना भगवान शिव (महादेव) से कर दी। जिस पर जलदाय मंत्री महेश जोशी समेत कई कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति जताते हुए हंगामा कर दिया और पारख की बयानबाजी की निंदा करते हुए इसे हिंदुओं की आस्था का अपमान बताया।

दरअसल राजस्थान वित्त-विनियोग विधेयक पर बहस के दौरान बीजेपी विधायक ज्ञानचंद पारख ने ''पीएम मोदी को महादेव का अवतार बता दिया। उन्होंने कहा, किसी जमाने में हर हर महादेव बोला जाता था, उसके बाद हजारों इष्ट हुए, हजारों नेता हुए, लेकिन उसके बाद कोई नारा लगा है तो वह हर हर मोदी का लगा है। हर हर राम और हर हर कृष्ण का नारा लगा, अब हर हर मोदी का नारा लगा है। जैसे महादेव ने विषपान किया था, वैसे ही मोदी को भी देश के विपक्षी पार्टी के नेताओं ने विषपान करवाया, पर उन्होंने कभी कोई बात मन में नहीं रखी। सारे जहर को पीकर भी उसने राष्ट्र हित में जो-जो काम करने थे, वे सारे काम किए। जब महादेव की तीसरी आंख खुलती है तो प्रलय होता है। मोदी की तीसरी आंख खुली तो कश्मीर से आतंकियों का सफाया हो गया। तीसरी आंख खुली तो पाकिस्तान की धरती पर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। पारख ने आगे कहा कि जब महादेव डमरू बजाते हैं तो राम मंदिर का निर्माण होता है। भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण होता है। धारा 370 और 35 ए की धारा खत्म हो जाती है।''

प्रधानमंत्री मोदी को महादेव का अवतार बताने पर जलदाय मंत्री महेश जोशी सहित कई कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति की। जोशी ने कहा कि महादेव की जगह कोई नहीं ले सकता। किसी इंसान से महादेव की तुलना करके हिंदुओं की आस्था का अपमान किया गया है। आपको महादेवजी को पूजना नहीं है, आपको केवल बयानबाजी करनी है। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि पारख अपने क्षेत्र में जाकर लोगों से कह दें कि महादेव की मूर्ति हटाकर मोदी की मूर्ति लगा दीजिए। यह तुलना गलत है। विधानसभा में इस पर कुछ देर के लिए हंगामे के हालात बने रहे।

नए विधायक को स्पीकर ने पूरक प्रश्न पूछना सिखाया

जयपुर, (वि.सं.)। विधानसभा में प्रश्नकाल काल के दौरान विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी को जब पूरक प्रश्न ठीक से नहीं पूछ पाईं। बार-बार असंगत पूरक प्रश्न पूछने पर स्पीकर ने ही विधायक दीप्ती महेश्वरी की सहायता करते हुए पूरक सवाल किया।

क्या गधों और कांग्रेस का कोई गठजोड़ है : राठौड़

जयपुर। विधानसभा में आज बहस के दौरान प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने पशुगणना में गधों की संख्या में आई कमी पर कहा कि जहां कांग्रेस सिकुड़ती गई उन राज्यों में गधे भी कम होते चले गए। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि गधों और कांग्रेस का कोई गठजोड़ है।

राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में ऊंट और गधों की संख्या में कमी आई है। राठौड़ ने कहा कि देश में गधों की संख्या कहां कम हुई, ये देखा तो आश्चर्य हुआ कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में मतलब जिन राज्यों में चुनाव हुए इन राज्यों में से 90 सीटों में से महज 55 सीट ही कांग्रेस के पास आई। राठौड़ ने कहा जहां आप सिकुड़ते चले गए, उन राज्यों में गधे भी कम होते गए। इस बीच सभापति जेपी चंदेलिया ने राठौड़ को टोका और कहा कि इन शब्दों का उपयोग ना करें। तब राठौड़ ने कहा ऐसा कदाचित नहीं है। राठौड़ की बात पर पलटवार करते हुए शिक्षा मंत्री ने संस्कृत श्लोक पढ़ा। राठौड़ जब सदन में व्यंगात्मक तरीके से कांग्रेस पर गधों के आंकड़ों को लेकर कटाक्ष कर रहे थे। तब सदन में मौजूद कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि आपको नहीं पता देश में सर्वाधिक गधे गुजरात में हैं।

भंवर सिंह भाटी घिरे सवालों में

जयपुर, (वि.सं.)। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक बलबीर सिंह लूथरा ने रायसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र में लंबित विद्युत कनेक्शनों से जुड़े सवाल के जवाब में मंत्री भंवर सिंह भाटी भी घिर गए। वे पहले नेता प्रतिपक्ष और फिर स्पीकर सीपी जोशी के सवाल का उचित जवाब नहीं दे पाए। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पूरक प्रश्न पूछा कि जिनका पैसा डिमांड जारी होने के बाद जमा हो गया फरवरी, 21 में ही, उन्हें आज मार्च, 22 तक भी कनेक्शन क्यों नहीं मिला। इसका जवाब नही मिलने पर अध्यक्ष ने पूछा कि डिमांड निकालते समय विभाग को क्या यह असेसमेंट नही है कि कितना सामान चाहिये होगा? स्पीकर के बार-बार सही जवाब देने के लिए टोकने पर भी वह असंगत जवाब देते रहे। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं।

बालमुकुंद ने जताया सीएम का आभार

जयपुर, (कासं)। लेखक और वरिष्ठ पत्रकार बाल मुकुंद ओझा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चूरू के किले के संरक्षण के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा पर उनका आभार व्यक्त किया है। राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को राजस्थान वित्त एवं विनियोग विधेयकों पर प्रत्युत्तर के दौरान यह घोषणा की।

अपेक्स बैंक की मोबाइल बैंकिग एवं व्हाट्सएप बैंकिग सेवा शुरू

सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने सोमवार को अपेक्स बैंक परिसर में मोबाइल बैंकिग एप, व्हाट्सएप बैंकिग, जयपुर रेलवे जंक्शन एवं कनकपुरा रेलवे स्टेशन पर एटीएम की सुविधा तथा सहकारी बैंकों के लिए न्यू एचआरएमएस पोर्टल के शुभांरभ पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया।

■ न्यू एचआरएमएस पोर्टल से सहकारी बैंकों के कार्मिकों को मिलेगी ऑनलाइन सुविधाएं

जयपुर, (का.सं.)। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि अपेक्स बैंक द्वारा मोबाइल बैंकिग सेवा, व्हाट्सएप बैंकिग सेवा, एटीएम सुविधा एवं न्यू एचआरएमएस पोर्टल प्रारंभ करने से उपभोक्ताओं एवं सहकारी बैंकों के कार्मिकों को आसानी से बैंकिग सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा बैंकिग क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों को सहकारी बैंक भी लागू कर रहे है। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों द्वारा उपभोक्ताओं को दी जा रही सुविधाओं में और विस्तार करने की आवश्यकता है।

आंजना सोमवार को अपेक्स बैंक परिसर में मोबाइल बैंकिग एप, व्हाट्सएप बैंकिग, जयपुर रेलवे जंक्शन एवं कनकपुरा रेलवे स्टेशन पर एटीएम की सुविधा तथा सहकारी बैंकों के लिए न्यू एचआरएमएस पोर्टल के शुभांरभ पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से और नवाचार किए जाए ताकि संस्थाओं में पारदर्शिता एवं डिलवरी सिस्टम को आसान बनाया जा सके।

उन्होंने कहा कि हर पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्थापना की जा रही है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों में आईटी का उपयोग कर आय को बढ़ाया जाए।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि ऋण माफी में ऑनलाइन व्यवस्था में आधार आधारित प्रमाण को लागू कर पोर्टल के माध्यम से ऋण माफी का लाभ वास्तविक किसान को दिलाया। ऋण माफी की कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है। ऋण वितरण में भी ऑनलाइन व्यवस्था शुरू कर फसली ऋण से वंचित किसान को ऋण वितरण से जोड़ा है। समर्थन मूल्य पर खरीद व्यवस्था में बॉयोमैट्रिक प्रणाली लागू कर किसान की खरीद सुनिश्चित की है। इसका फायदा छोटे किसानों को भी मिला है। मोबाइल बैंकिग सेवा रू. शीर्ष सहकारी बैंक द्वारा तैयार किये गये मोबाईल एप्प से बैंक के ग्राहक अपने मोबाईल से अपने खातों की जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ बैलेन्स इन्क्वायरी, मिनि स्टेटमेन्ट, कस्टमाइज्ड स्टेटमेन्ट, एम-पासबुक प्राप्त कर सकेंगे। बैंक के ग्राहक, के माध्यम से किसी भी बैंक के किसी भी ग्राहक को राषि हस्तांतरित कर सकेंगे। साथ ही ग्राहकों को भारत बिल पेमन्ट सिस्टम द्वारा इलेक्ट्रिक सिटी, पानी, गैस, डीटीएच, फास्टेग आदि की सेवायें मोबाईल एप्प पर प्राप्त हो सकेंगी।

कोई एक नेता हो तो मैं पटा लूं, लेकिन बीजेपी में तो सीएम के कई दावेदार : अशोक गहलोत

ईस्टर्न कैनाल की पैरवी केन्द्र सरकार से करने की मांग विपक्ष से करते हुए मुख्यमंत्री ने चुटकी ली

-विधानसभा संवाददाता-

■ 'प्रधानमंत्री मोदी के यहां पर वसुंधराजी का हो न हो, कटारियाजी की बात में वजन होगा, इसलिए आप मन से भय निकालकर मोदी-अमित शाह से मांग करो'

जयपुर। राजस्थान के 13 जिलों के पेयजल से जुड़ी ईस्टर्न कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने की मांग सोमवार को एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सदन में बीजेपी नेताओं के सामने रखी।

सीएम ने कहा कि ईस्टर्न कैनाल को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने में बीजेपी नेता मदद करें। यह 13 जिलों का मामला है। बीजेपी नेता इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाएं अन्यथा अगले चुनावों में 13 जिलों में साफ हो जाओगे। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री भी हमारे राजस्थान के हैं। अब बीजेपी में एक नेता हो तो मैं पटा लूं कि राज्य हित में दिल्ली जाकर पैरवी करनी है, लेकिन यहां तो अनेकों नेता हैं। केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत साहब, गुलाबचंद कटारिया साहब, कैलाश मेघवाल साहब, सतीश पूनिया साहब और वासुदेव देवनानी साहब सीएम के दावेदार हैं। और भी कई साहब हैं, जो सीएम के दावेदार हैं, हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला, हमारे ओम माथुर साहब भी सीएम दावेदार हैं। एक नेता हो तो मैं पटा लूं कि साथ चलो, लेकिन बीजेपी में तो कई नेता हैं।

इसके बाद गहलोत ने चुटकी लेते हुए नेता प्रतिपक्ष से कहा कि ''कटारियाजी आप आरएसएस कैडर के हो, आपकी बात कौन टाल सकता है। भय को मन से निकालो और पीएम के यहां जाकर पैरवी करो। पीएम के यहां आपकी बात का वजन होगा, चाहे वसुंधराजी की बात का वजन हो न हो, लेकिन आपकी बात का वजन होगा, आप कैडर के आदमी हो। आप ईस्टर्न कैनाल पर प्रधानमंत्री से जाकर मांग करोगे तो आपका सम्मान भी बढेगा और पीएम भी मुझे लगता है राजी होंगे। आप डर निकालो और बतौर नेता प्रतिपक्ष अपनी भूमिका निभाकर राजस्थान की पैरवी करें।

गहलोत ने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मांग करते हुए ही बीजेपी के नेता डरते हैं। मोदीजी और अमित शाहजी का पता नहीं क्यों एक भय बैठ गया है कि हक की बात भी नहीं करते। मार्गदर्शक मंडल बन गया वो अलग बात है, लेकिन बाकी नेता मांग ही नहीं करते।

'कटारियाजी! आपकी बीपी अप-डाउन चलती है'

जयपुर। मुख्यमंत्री ने वित्त-विनियोग विधेयक का जवाब देते हुए नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया पर चुटकियां ली। अशोक गहलोत ने कहा कि ''कटारियाजी! आप बीपी कंट्रोल रखकर बोला कीजिए। आप जब भाषण देते हैं तो बीपी अप-डाउन चलता रहता है। आप इस पर कंट्रोल रखिए नहीं तो आपके घर वाले मुझे उलाहना देंगे कि आप इनका ध्यान नहीं रखते। सदन का नेता हूं तो आपके फैमिली वालों का इतना हक तो मेरे पर बनता है।'' पुनः चुटकी लेते हुए कहा कि ''आपको अंदाज बदलना चाहिए, आप भावुक होकर बोलते हो, लेकिन आंकड़ों को भी इस तरह से पेश करते हो, जैसे पत्थर में जान डाल दी।''